



04 - राहुल गांधी का हिन्दू धर्म बनाम आरएसएस का हिंदुत्व



05 - सियासी समीकरणों का नया दौर

A Daily News Magazine

भोपाल

गुरुवार, 18 जुलाई, 2024



भोपाल एवं इंदौर से एक साथ प्रकाशित



06- आवेदक प्रेमशंकर मिश्रा ने खोली वन विभाग के भ्रष्टाचार की पोल, राज्यपाल...



07- आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर से बेटीयों में आत्म-विश्वास बढ़ता है

वर्ष 21 अंक 311 नगर संस्करण, पृष्ठ -8, मूल्य रु.- 2 (डाक पंजीयन संख्या: म.प्र./भोपाल/4-391/2018-20)



subahsaverenews@gmail.com
facebook.com/subahsaverenews
www.subahsavere.news
twitter.com/subahsaverenews

सुप्रभात

कंकाल बाहर निकल आये हैं
उन सब धर्मशास्त्रों के,
जिन्हें बड़ी चतुराई से दफना दिया था।
तुम नहीं पहचानते इन कंकालों को,
ये ही दिखाई देते हैं आजकल
बड़े-बड़े शादी-घरों में, धर्म के प्रतिष्ठानों में।
कुछ बोलते नहीं ये,
कंकाल ही तो हैं बेवारे।
लेकिन वे सब काम कर जाते हैं,
जी आप करवाना चाहते हैं।
कंकालों की भीड़ उमड़ रही है,
लोग इन्हें उठा-उठाकर बैठा रहे हैं
स्वर्ण सिंहासन पर,
इनके पाँव पखार रहे हैं
कुबेरों के यूथ के यूथ घरती पर।
अभी ये बने रहेंगे तब तक,
जब तक कोई पथर नहीं उखलता,
आकाश में सुराख नहीं होता।

- मुत्तलीधर चांदनीवाला

उत्तर प्रदेश में राजनीतिक सरगर्मी बड़ी

प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने पीएम को दी खींचतान की रिपोर्ट

सीएम योगी राजभवन पहुंचे, केशव के बगावती तेवर के बाद सियासी हलचल बड़ी

लखनऊ (एजेंसी)। केशव मौर्य के लगातार बगावती तेवर के बाद उत्तर प्रदेश में राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने बुधवार शाम को पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। उन्होंने उत्तर प्रदेश में सरकार और संगठन के बीच मौजूदा खींचतान की रिपोर्ट दी।

इधर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राज्यपाल आनंदी बेन पटेल से मुलाकात करने राजभवन पहुंच गए हैं। हालांकि इसे शिष्टाचार भेंट बताया जा रहा है। इससे पहले योगी ने यूपी में दस विधानसभा सीटों पर होने वाले उप-चुनाव को लेकर मंत्रियों के साथ बैठक की। लोकसभा चुनाव में भाजपा को हुए सीटों के तगड़े नुकसान के बाद से



ही खींचतान देखी जा रही है। भाजपा और सहयोगी पार्टी के नेता उत्तर प्रदेश सरकार के कामकाज पर सवाल उठा रहे हैं। पिछड़ों के सबसे बड़े नेता केशव मौर्य लगातार योगी सरकार पर निशाना साध रहे हैं। वह बार-बार कह रहे हैं कि कार्यकर्ता और संगठन सरकार से बड़ा है।

आगामी चुनावों पर चर्चा करने के लिए आयोजित की गई थी बैठक: वित्त मंत्री सुरेश खन्ना

मिली जानकारी के मुताबिक, वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि बैठक विशेष रूप से आगामी चुनावों पर चर्चा करने के लिए आयोजित की गई थी और हम उन सभी 10 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल करेंगे जहां उपचुनाव होने हैं। प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों... कटेहरी (अंबेडकरनगर), करहल (मैनपुरी), मिल्लीपुर (अयोध्या), मीरापुर (मुजफ्फरनगर), गाजियाबाद, मझवा (मिर्जापुर), सीसामऊ (कानपुर नगर), खैर (अलीगढ़), फूलपुर (प्रतापगढ़) और कूदरकी (मुरादाबाद) पर उपचुनाव होने हैं। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के कंत्रोज से लोकसभा के लिए चुने जाने के बाद करहल (मैनपुरी) विधानसभा सीट से इस्तीफा दे दिया।

क्या बंगाल में भाजपा की सियासी पारी हो रही है कमजोर ?

श्रेयसी डे

विगत 10 जुलाई को हुए विधानसभा उपचुनाव में तृणमूल कांग्रेस ने भाजपा से रायगंज, बागदा और राणाघाट दक्षिण की सीटें छीन लीं, जबकि मानिकतला सीट पर अपना कब्जा बरकरार रखा। ममता बनर्जी ने इसे 'लोगों की जीत' बताया। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सियासी पारी लगातार कमजोर होती जा रही है, चार विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनावों के नतीजों से राज्य में उसकी राजनीतिक ताकत में लगातार गिरावट का संकेत मिलता है।

ममता बनर्जी की अगुआई वाली तृणमूल कांग्रेस ने 10 जुलाई को हुए मतदान में रायगंज, बागदा, राणाघाट दक्षिण और मानिकतला की सभी चार सीटों पर जीत हासिल की। चारों सीटों पर भाजपा के उम्मीदवार दूसरे स्थान पर रहे, जबकि कांग्रेस ने दोनों सीटों (रायगंज और बागदा) पर अपनी जमानत गंवा दी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माक्सवादी) ने दो सीटों (राणाघाट दक्षिण और मानिकतला) पर अपनी जमानत गंवा दी। 2021 के विधानसभा चुनावों में भाजपा ने रायगंज, बागदा और राणाघाट दक्षिण सीटें जीतीं, लेकिन उसके तीनों विधायक कृष्ण कल्याणी, विश्वजीत दास और मुकुट मणि अधिकारी अंततः टीएमसी में शामिल हो गए। हाल ही में संपन्न लोकसभा चुनावों में कृष्ण कल्याणी और मुकुट मणि अधिकारी रायगंज और राणाघाट में भाजपा उम्मीदवारों से हार गए, लेकिन उन्हें विधानसभा उपचुनाव के लिए मैदान में उतारा गया, जिसमें उन्होंने जीत हासिल की। रायगंज में कृष्ण कल्याणी ने भाजपा

के मानस कुमार घोष को 50,077 मतों के अंतर से हराकर विधानसभा सीट पर कब्जा किया।

भाजपा सांसद और केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर के लोकसभा क्षेत्र में आने वाली मतुआ बहुल सीट बागदा में टीएमसी आठ साल बाद वापसी करने में सफल रही। तृणमूल की मधुपर्णा ठाकुर, जो 25 साल की उम्र में बागदा से विधानसभा के लिए चुनी गई हैं, सदन की सबसे कम उम्र की सदस्य होंगी। वे टीएमसी सांसद ममता बाला ठाकुर की बेटी और शांतना ठाकुर की चचेरी बहन हैं। मधुपर्णा ने भाजपा के बिनय कुमार विश्वास को 33,455 मतों के अंतर से हराकर सीट जीती। राणाघाट दक्षिण में टीएमसी के मुकुट मणि अधिकारी ने मनोज कुमार विश्वास को 39,048 मतों के अंतर से हराया।

इसी तरह, मानिकतला में जहां मौजूदा विधायक और राज्य मंत्री शदान पांडे की मृत्यु के कारण उपचुनाव कराए गए, उनकी विधवा सुनी पांडे ने भाजपा के कल्याण चौबे को 62,312 मतों के आरामदायक अंतर से हराया, जिससे वह सीट बरकरार रही जो 2011 से परिवार के पास थी। लेकिन राजनीतिक विश्लेषक उदयन बंदोपाध्याय के अनुसार, यह कहना अभी जल्दबाजी होगी कि विधानसभा उपचुनाव के नतीजों को पश्चिम बंगाल में भाजपा की घटती राजनीतिक ताकत के संकेत के रूप में लिया जा सकता है।

उन्होंने कहा, 'हम लोकसभा चुनाव के नतीजों के 36 दिनों के भीतर हुए उपचुनाव के नतीजे देख रहे हैं। इसलिए, बंगाल की राजनीति में टीएमसी के लिए भावनाओं का बढ़ना कोई असामान्य बात नहीं है। यह कहना अभी जल्दबाजी होगी कि भाजपा का प्रभाव कम

हो रहा है। दूसरी ओर, यह तृणमूल के लिए एक तरह से लाभ है क्योंकि वह उसी तरह का राजनीतिक रवैया दिखा रही है जैसा भाजपा को दिखाना चाहिए।'।

उन्होंने कहा, 'उम्मीदवार के चयन से लेकर मतुआ भावना तक, तृणमूल नेतृत्व ने एक ही कार्ड को अलग-अलग रंग में खेला है। साथ ही, यह भी स्वीकार करना होगा कि राजनीतिक बयानबाजी और संगठनात्मक व्यवहार के मामले में तृणमूल अभी भाजपा से बहुत आगे है।' पिछले महीने संपन्न हुए लोकसभा चुनावों में भाजपा को पश्चिम बंगाल में करारा झटका लगा, जहां उसे केवल 12 सीटें मिलीं - 2019 की तुलना में छह कम- जबकि टीएमसी ने राज्य की 42 लोकसभा सीटों में से 29 सीटें जीतीं।

लेकिन वोट शेयर भाजपा के लिए थोड़ी राहत लेकर आया। 2019 के आम चुनाव की तुलना में इसका वोट शेयर मात्र 2 प्रतिशत अंक घटकर 38 प्रतिशत रह गया, जबकि टीएमसी का वोट शेयर भी 2 प्रतिशत अंक घटकर 46 प्रतिशत रह गया। राज्य भाजपा नेताओं ने विधानसभा उपचुनावों में पार्टी के खराब प्रदर्शन के पीछे मुख्य कारणों के रूप में 'धांधली' और कथित चुनाव संबंधी हिंसा को जिम्मेदार ठहराया। भाजपा के कल्याण चौबे ने कहा, 'चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष नहीं थे। धांधली हुई और भाजपा कार्यकर्ताओं को धमकाया गया। इसलिए, हम ये परिणाम देख रहे हैं।'।

भाजपा सांसद समिक भट्टाचार्य ने मीडिया से कहा, 'हम उपचुनाव पूरे मन से नहीं लड़ सके। कुछ मामलों में लोगों को गलत संदेश गया। मतदाताओं को शत्रुतापूर्ण माहौल में मतदान करना पड़ा, जो बागदा और राणाघाट

दक्षिण में स्पष्ट था, लेकिन धैर्य रखिए, हम इसे बदल देंगे।' दूसरी ओर, ममता बनर्जी ने मुंबई की दो दिवसीय यात्रा के बाद राज्य लौटने पर परिणामों का स्वागत किया।

उन्होंने कहा, 'इस बार जिन चार सीटों पर चुनाव लड़ा जा रहा है, उनमें से तीन पर भाजपा ने लोकसभा और विधानसभा दोनों में जीत हासिल की है। हमने न केवल अपनी सीट बरकरार रखी है, बल्कि अन्य तीन पर भी जीत हासिल की है। यह टीएमसी के लिए चार में से चार है। हम लोगों का आधार व्यक्त करते हैं। यह लोगों की जीत है।'।

इंडिया ब्लॉक के भीतर एकता को मजबूत करने के प्रयास में, उन्होंने यह भी कहा, 'भाजपा दो सीटों को छोड़कर पूरे देश में उपचुनाव हार गई है जेजे हर जगह हार गए हैं और इस प्रकार पूरे देश में रुझान भी भाजपा के खिलाफ है। यह रुझान बहुत स्पष्ट है। लोगों का जनदेश एनडीए के पक्ष में नहीं बल्कि इंडिया के पक्ष में है। एनडीए में सभी दलों को एक साथ मिलाकर 46 प्रतिशत वोट मिले, जबकि इंडिया गठबंधन दलों को 51 प्रतिशत वोट मिले। जनदेश उनके खिलाफ है।'।

राजनीतिक विश्लेषक क्षिंधे भट्टाचार्य के अनुसार, हालांकि, सत्तारूढ़ पार्टी को आमतौर पर उपचुनावों में बढ़त मिलती है, लेकिन 'यह जीत टीएमसी के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि लोकसभा चुनाव में हारने वाले दो दलबदलू जीत गए हैं।' उन्होंने कहा, 'ये नतीजे भाजपा के लिए झटका हैं, जिसके लिए कार्यकर्ताओं और समर्थकों का मनोबल बनाए रखना मुश्किल हो सकता है।'।

(दि प्रिंट हिंदी में प्रकाशित लेख के संपादित अंश)

सीएम डॉ. मोहन यादव दिल्ली पहुंचे

● नइड़ा-शाह से मुलाकात के बाद मंत्रियों को मिल सकते हैं जिलों के प्रभार

रावत का विभाग भी हो सकता है तय



भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव बुधवार सुबह 10 बजे दिल्ली पहुंचे थे। वे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सहित पार्टी के सीनियर लीडर्स से मुलाकात कर सकते हैं। कैबिनेट गठन के 6 महीने बाद अब मंत्रियों को प्रभार के जिलों की लिस्ट पर भी मुहर लग सकती है। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस समारोह में मंत्री अपने प्रभार के जिलों में ध्वजारोहण कर सकते हैं। मुख्यमंत्री को मंगलवार शाम को ही दिल्ली जाना था, लेकिन किसी कारण से दौरा कैसिल हो गया। सूत्रों की मानें तो मंत्रियों को जिलों का प्रभार देने में क्षेत्रीय और जातिगत समीकरणों के साथ ही सीनियरिटी का भी ध्यान रखा जाएगा। यह भी देखा जाएगा कि प्रभार के जिलों की दूरी इतनी हो कि महीने में तीन से पांच दौर किए जा सकें।

मंत्री रामनिवास रावत के विभाग पर भी फैसला

विजयपुर से कांग्रेस के टिकट पर छठवीं बार के विधायक रामनिवास रावत 8 जुलाई को मोहन सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं। नौ दिन बाद भी रावत को विभाग नहीं दिया जा सका है। दिल्ली का विभाग भी तय हो सकता है। रावत विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे चुके हैं।

यूजीसी ने जारी किए दिशा-निर्देश

कॉलेज कैटीन में नहीं मिलेंगे समोसा कचौरी जैसे अनहेल्दी फूड आइटम्स

नईदिल्ली (एजेंसी)। देश के कॉलेजों में बड़ी संख्या में छात्र पढ़ते हैं। ऐसे में छात्रों को सुविधा के लिए कॉलेजों में कैटीन भी खुली रहती है। अगर आप भी कॉलेज कैटीन से खाना खाते हैं, तो यह खबर आपके लिए ही है। दरअसल, यूजीसी ने हाल ही में विश्वविद्यालयों और डिग्री कॉलेजों की कैटीन में मिलने वाले खाने को लेकर एक नोटिस जारी किया है। इस नोटिस में अनहेल्दी फूड आइटम्स की बिक्री बंद करने के निर्देश दिए गए हैं।

इस नोटिस के बाद, जल्द ही आपको अपने कॉलेज की कैटीन में समोसा, नूडल्स, ब्रेड पकीड़ा आदि जैसे कई अनहेल्दी फूड आइटम्स खाने को नहीं मिलेंगे। यूजीसी ने नोटिस में निर्देश दिया है कि उच्च शिक्षा संस्थानों में संचालित हो रहे कैटीन द्वारा अब सिर्फ हेल्दी फूड ही परोसे जाएंगे।

आधिकारिक नोटिस के अनुसार, जैसा कि आप जानते हैं, नेशनल एडवोकेसी इन पब्लिक इंटरैस्ट (एनपीआई) पोषण पर एक राष्ट्रीय थिंक टैंक है, जिसमें महामारी विज्ञान, मानव



पोषण, सामुदायिक पोषण और बाल चिकित्सा, चिकित्सा शिक्षा, प्रशासन, सामाजिक कार्य और प्रबंधन में स्वतंत्र विशेषज्ञ शामिल हैं। बड़ते मोटापे, मधुमेह और अन्य गैर-संचारी रोगों (एनसीडी) पर चिंतित, सामान्य एनसीडी (2017-2022) की

रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय बहु-क्षेत्रीय कार्य योजना (एनएमएपी) के त्वरित कार्यान्वयन के लिए एनएपी ने शैक्षणिक संस्थानों में अनहेल्दी फूड की बिक्री पर रोक लगाने और कैटीनों में स्वस्थ भोजन विकल्पों को बढ़ावा देने का अनुरोध किया है।

यूजीसी पहले भी जारी कर चुका है एडवाइजरी

नोटिस में यूजीसी ने कहा है कि इस सम्बन्ध में उच्च शिक्षा संस्थानों को पहले भी, 10 नवंबर 2016 और 21 अगस्त 2018, एडवाइजरी जारी जा चुकी है। इस क्रम में संस्थानों को एक बार फिर से चेताया जाता है कि वे अपनी कैटीन में अनहेल्दी फूड की बिक्री पर रोक लगाएं और सिर्फ हेल्दी फूड ही परोसे जाने को बढ़ावा दें। ऐसा करके हम गैर-संचारी रोगों की लगातार बढ़ रही महामारी पर रोक लगाने में सक्षम हो सकेंगे।

सिद्धारमैया ने कर्नाटक में 100 प्रतिशत कोटा बिल पर पोस्ट हटाई

श्रम मंत्री की सफाई-

● यह 50 प्रतिशत और 70 प्रतिशत है



बेंगलुरु (एजेंसी)। कर्नाटक में प्राइवेट कंपनियों में गुप सी और डी में स्थानीय लोगों को 100 प्रतिशत आरक्षण देने का फैसला विवादों में घिर गया है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने 16 जुलाई को इसकी घोषणा की थी। 24 घंटे के अंदर ही उन्होंने सोशल मीडिया पर 100 प्रतिशत कोटा बिल को लेकर की गई पोस्ट हटा ली। सीएम के पोस्ट डिलीट करने पर राज्य के लेबर मिनिस्टर संतोष लाड ने बुधवार को सफाई दी- कर्नाटक में प्राइवेट कंपनियों की नौकरियों में नॉन-मैनजमेंट पोस्ट के लिए रिजर्वेशन 70 प्रतिशत और मैनेजमेंट लेवल के स्टाफ के लिए 50 प्रतिशत तक सीमित है।

सबका साथ, सबका विकास की जरूरत नहीं : शुभेंदु अधिकारी

कहा-

● भाजपा को अल्पसंख्यक मोर्चा बंद कर देना चाहिए, जो हमारे साथ

कोलकाता (एजेंसी)। पश्चिम बंगाल भाजपा विधायक और विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने बुधवार (17 जुलाई) को कहा, 'सबका साथ, सबका विकास', लेकिन अब हम यह नहीं कहेंगे। अब हम कहेंगे जो हमारा साथ, हम उनके साथ... 'सबका साथ, सबका विकास कहना बंद



करो'। पार्टी की राज्य कार्यकारिणी की बैठक में बोले, भाजपा को अल्पसंख्यक मोर्चा की भी जरूरत नहीं है। हम जीतेंगे, हम हिंदुओं को बचाएंगे और संविधान को बचाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में सबका साथ, सबका विकास का नारा दिया था। शुभेंदु ने कुछ घंटे बाद सफाई दी, पीएम के बयान से कोई लेना-देना नहीं।

केदारनाथ से 228 किलो सोना गायब होने का आरोप

समिति के अध्यक्ष बोले-

● स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सनसनी न फैलाएं, सबूत है तो कोर्ट जाएं

नई दिल्ली (एजेंसी)। ज्योतिमठ के शंकराचार्य 'स्वामी' अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने 15 जुलाई को केदारनाथ मंदिर से 228 किलो सोना गायब होने का आरोप लगाया था। इस पर श्री बद्रीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने कहा- स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सिर्फ सनसनी फैलाना चाहते हैं। सबूत हैं तो सुप्रीम कोर्ट या हाईकोर्ट जाएं। अजेंद्र अजय ने कहा- मैं स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का सम्मान करता हूं, लेकिन वे दिनभर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं। विवाद खड़ा करना, सनसनी फैलाना और चर्चाओं में बने रहना अविमुक्तेश्वरानंद की आदत है।

महाराष्ट्र की शिंदे सरकार की 'लाइला भाई योजना'

युवा बनेंगे 'लाइले', हर महीने मिलेंगे 10 हजार रुपए

नई दिल्ली (एजेंसी)। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले ही मौजूदा सरकार ने सत्ता में वापसी के लिए घोषणाओं की झड़ी लगा दी है। महाराष्ट्र सरकार ने लाइली बहना के बाद अब 'लाइला भाई योजना' लाने का एलान किया है। इस योजना के तहत 12वीं की परीक्षा पास करने वाले छात्रों को हर महीने 6 हजार रुपये दिए जाएंगे। इसके अलावा इस योजना के तहत डिप्लोमा कर रहे छात्रों को हर महीने आठ हजार और ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी करने वाले स्टूडेंट्स को हर महीने 10 हजार रुपये देने का फैसला किया है।

सीएम शिंदे ने इस योजना को लेकर क्या कहा?

इस योजना का एलान करते हुए सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि इस योजना के तहत, हमारी सरकार राज्य के युवाओं को उन कारखानों में अप्रेंटिसशिप करने के लिए पैसे देने जा रही है जहां वे काम करेंगे। इस योजना के तहत हमारे युवाओं को फैक्ट्रियों में



अप्रेंटिसशिप मिलेंगी और सरकार उन्हें वजीफा देगी। सीएम शिंदे ने इस योजना को लेकर कहा कि सरकार की नजर में लड़का और लड़की में कोई फर्क नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि इतिहास में यह पहली बार है कि किसी सरकार ने ऐसी योजना लांच की है। आगे उन्होंने कहा कि इस योजना से हमने बेरोजगारी का समाधान ढूंढ लिया है।

'लाइला भाई स्कीम' का किसे मिलेगा लाभ?

इस योजना के तहत 12वीं पास करने वाले युवाओं को 6 हजार रुपये प्रति माह दिया जाएगा। तो, डिप्लोमा करने वाले युवाओं को 8 हजार रुपये दिए जाएंगे। वहीं, ग्रेजुएट युवाओं को 10 हजार रुपये प्रति माह दिए जाएंगे।

योग्यता	राशि
12वीं पास	6 हजार रुपये
डिप्लोमा	8 हजार रुपये
ग्रेजुएट	10 हजार रुपये

हरियाणा सरकार का अग्निवीरों को तोहफा

● सरकारी नौकरी में मिलेगा 10 फीसदी आरक्षण

हरियाणा (एजेंसी)। हरियाणा सरकार ने अग्निवीरों के लिए बड़ी घोषणा की है। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने अग्निवीरों को गुप बी और सी में सरकारी पदों के लिए निर्धारित अधिकतम आयुसीमा में तीन साल की छूट देने का एलान किया है। इसके साथ ही उन्होंने सिविल पदों पर अग्निवीरों की सीधी भर्ती पर आरक्षण की भी घोषणा की है।



हरियाणा सरकार देगी 10 फीसदी का आरक्षण- सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि हमारी सरकार 10 फीसदी आरक्षण देगी। अग्निवीर पीएम मोदी की लोकहित योजना है। अग्निवीर को रूप बी और गुप सी में अग्निवीरों को प्राथमिकता दी जाएगी। अग्निवीरों के घायल होने पर एक कमेटी जांच रिपोर्ट पूरी होने पर इलाज के पैसे दिए जाएंगे। इसके लिए हर जिले में कमेटी का गठन किया जाएगा। वहीं, पीड़ित की मौत हो जाने पर परिजनों को मुआवजा मिले। इसके साथ ही आर्म्स लाइसेंस की सुविधा सरकार अग्निवीरों को देगी। हरियाणा सीएम नायब सैनी ने कहा कि पुलिस, माइनिंग गार्ड की भर्ती कैटेगरी में 10 फीसदी का आरक्षण मिलेगा



लखनऊ/नईदिल्ली। नेपाल से सटे उत्तर प्रदेश के 16 जिलों में बाढ़ के हालात लगातार बने हुए हैं। यहां तीन नदियां खतरे के निशान के ऊपर बह रही हैं। राप्ती नदी, बूढ़ी राप्ती और क्यूनो नदी के उफान पर होने के कारण गोरखपुर, सिद्धार्थ नगर और गोंडा में हालात सबसे ज्यादा खराब हैं। वाराणसी का रक्षेत्र महादेव मंदिर गंगा में डूब गया है। यह दुनिया का पहला झुका हुआ मंदिर है। पिछले 24 घंटे में बारिश से संबंधित घटनाओं के कारण 6 लोगों की मौत हुई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने बताया कि सभी की मौत डूबने से हुई है। इसके अलावा कर्नाटक में तेज बारिश के बाद लैंडस्लाइड के कारण 4 लोगों की मौत हो गई। उधर, बिहार में भी बेतिया, बगहा, सीतामढ़ी, मधेपुरा, अररिया समेत कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। 24 से ज्यादा निचले इलाकों के गांव में बाढ़ का पानी घुस चुका है। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश समेत 9 राज्यों में बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है।

9 राज्यों में बहुत भारी बारिश का अनुमान- मौसम विभाग ने बुधवार 17 जुलाई को मध्य प्रदेश,



राजस्थान, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और उत्तराखंड यानी 9 राज्यों में बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी है। वहीं, 10 राज्यों तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, मणिपुर, नगालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, पंजाब और हरियाणा में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है।

राजस्थान के 2 शहीदों का अंतिम संस्कार

जयपुर/झुंझुनू (एजेंसी)। जम्मू-कश्मीर में आतंकी हमले में शहीद राजस्थान के झुंझुनू जिले के 2 जवानों का अंतिम संस्कार शोही देर में होगा। शहीदों के सम्मान में स्थानीय लोगों ने उनके पार्थिव शरीर को लेकर तिरंगा यात्रा निकाली। इस यात्रा में भारी भीड़ उमड़ी। शहीद बिजेंद्र सिंह दौराता झुंझुनू के सिंघाना थाना इलाके के खुबा की दाणी (डुमोली कला) के रहने वाले थे और अजय सिंह भी इसी इलाके में भेसावता कला के रहने वाले थे। बिजेंद्र सिंह की पार्थिव देह जब उनके घर पहुंची तो उन्हें देखकर मां बिलख पड़ी। वहीं बिजेंद्र सिंह के बेटे ने अपने दादा की गोद में बैठकर पिता के अंतिम दर्शन किए।

कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में धोती पहने बुजुर्ग को नहीं मिला प्रवेश

कन्नड़ किसानों के संगठन ने मॉल के बाहर किया विरोध

बेंगलुरु (एजेंसी)। कर्नाटक में एक बार फिर हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। कुछ महीनों पहले बेंगलुरु मेट्रो में एक किसान को प्रवेश नहीं मिला था अब अपने बेटे के साथ मॉल में फिल्म देखने पहुंचे एक बुजुर्ग को प्रवेश नहीं मिला, क्योंकि बुजुर्ग ने धोती पहने के साथ सिर पर साफ़ी बांधी हुई थी। यह घटना कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में सामने आई है। सोशल मीडिया पर सामने आए एक वीडियो में दावा किया गया है कि बुजुर्ग को धोती पहने होने के कारण मॉल में प्रवेश नहीं दिया गया। बुजुर्ग को उसका बेटे ऑनलाइन टिकट बुक करने के बाद फिल्म दिखाने के लिए जीटी वर्ल्ड मॉल लेकर गया था। इस घटना ने एक बार फिर से कई सवाल खड़े कर दिए हैं कि आखिर सिद्धारमैया सरकार के सख्त रवैए के बाद भी ऐसी घटना की पुनरावृत्ति क्यों हुई है। बेंगलुरु के जीटी वर्ल्ड मॉल में यह घटना घटी। बेटे ने अपने पिता को फिल्म दिखाने के लिए टिकट बुक किया था। जब बेटा अपने पिता को लेकर मॉल पहुंचा तो सिक्योरिटी स्टॉफ ने प्रवेश देने से मना कर दिया है। सिक्योरिटी गार्ड ने कहा कि ऐसी ड्रेस पहनकर मॉल में जाने की अनुमति नहीं है। गार्ड ने कहा कि प्रवेश के लिए उन्हें पैट पहनकर आना होगा।



नई दिल्ली (एजेंसी)। सरकार ने नीति आयोग का पुनर्गठन किया है। नई सरकार बनने और मंत्रिपरिषद में कुछ नए मंत्रियों को जगह मिलने के बाद आयोग का पुनर्गठन किया गया है। आयोग के उपाध्यक्ष और पूर्णकालिक सदस्यों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। हालांकि इस पुनर्गठन में सहयोगी दलों के सदस्यों की भी एंट्री हुई है। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में बीजेपी अपने सहयोगी दलों का खासा ध्यान रख रही है। सहयोगी दलों के पांच मंत्री हुए शामिल- सरकार ने मंगलवार जिस नीति आयोग का पुनर्गठन किया उसमें आमंत्रित सदस्यों की संख्या 5 से बढ़ाकर 11 कर दी गई है। इसमें बीजेपी के सहयोगी दलों के पांच

मंत्री - एच डी कुमारस्वामी (जेडीएस), जीतन राम मांझी (एचएमएम), राजीव रंजन सिंह (जेडीयू), के आर नायडू (टीडीपी) और चिराग पासवान (एलजेपी-राम विलास) शामिल हैं। जिन सहयोगी दलों को शामिल किया गया है, उनमें कुमारस्वामी के पास भारी उद्योग और इस्पात विभाग है, मांझी के पास सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग है, राजीव रंजन सिंह उर्फ लालन सिंह के पास मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी विभाग है, नायडू के पास नागरिक उड्डयन विभाग है और चिराग पासवान के पास खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विभाग है। किसको इस बार नहीं मिली जगह- केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और अश्विनी वैष्णव, जो पहले विशेष आमंत्रित थे, इस बार सूची में नहीं हैं। गडकरी, वीरेंद्र कुमार और राव इंद्रजीत सिंह भी पहले विशेष आमंत्रित थे। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को बतौर पदेन सदस्य शामिल किया गया है।

क्षिप्रा के घाट श्रद्धालुओं के लिये बनेंगे सुविधायुक्त

निरंतर बना रहेगा क्षिप्रा में जल-प्रवाह

● मुख्यमंत्री डॉ. यादव की पहल पर कार्य योजना हुई तैयार

भोपाल (नप्र)। सिंहस्थ-2028 में क्षिप्रा नदी में जल-प्रवाह को निरंतर बनाये रखने के लिये मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की पहल पर विस्तृत कार्य योजना तैयार की गई है। इसमें बैराजों का निर्माण किया जायेगा। कान्ह नदी के व्यपवर्तन से प्रदूषण को रोका जा सकेगा। क्षिप्रा नदी पर श्रद्धालुओं की स्नान सुविधा के लिये सुविधाजनक घाटों का निर्माण होगा। घाटों के निर्माण में लगने वाले पत्थर और अन्य सामग्री का



चयन विशेषज्ञों द्वारा किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों और अभियंताओं को व्यापक अध्ययन और शोध के बाद कार्य योजना तैयार कर क्रियान्वयन के निर्देश दिए हैं। श्रद्धालुओं को आचमन और स्नान में नहीं होगी कोई असुविधा- क्षिप्रा के जल को प्रदूषण मुक्त करने के लिए कान्ह नदी के व्यपवर्तन, कान्ह नदी पर 11 बैराजों और क्षिप्रा नदी पर 18 बैराजों का निर्माण इंदौर, उज्जैन और देवास जिले में प्रस्तावित है। इससे सिंहस्थ के लिए क्षिप्रा नदी में निरंतर जल प्रवाह बना रहेगा। क्षिप्रा नदी पर स्नान के बेहतर प्रबंध किये जा सकेंगे। कार्य योजना में क्षिप्रा नदी में सेवरखेड़ी बैराज से मानसून के समय जल का उद्घन करते हुए 51 मि.घ.मी. जल, पूर्व निर्मित सिलाखेड़ी जलाशय के विस्तारीकरण से भरे जाने की व्यवस्था की जाएगी, जिससे मानसून के अलावा अन्य मौसमों में भी क्षिप्रा नदी में जल निरंतर प्रवाहित होता रहेगा। श्रद्धालुओं एवं पर्यटकों को आचमन और स्नान इत्यादि में किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने निर्माण एजेंसियों को हिदायत दी है कि कार्य योजना के सभी कार्य समय-सीमा में गुणवत्तापूर्वक किये जाएं। ध्यान रखा जाए कि क्षिप्रा नदी पर प्रस्तावित संरचनाओं, प्रस्तावित बैराजों के निर्माण तथा आवश्यक घाटों के निर्माण से स्थानीय निवासियों को कोई असुविधा न हो। इन घाटों पर श्रद्धालुओं को मिलेंगी पर्याप्त सुविधाएँ-प्रस्तावित कार्य योजना के अनुसार उज्जैन में शनि मंदिर से वी.आई.पी. घाट तक 1500 मीटर, वी.आई.पी. घाट से जीवनखेड़ी ब्रिज तक 7175 मीटर, जीवनखेड़ी ब्रिज से वाकणकर ब्रिज तक 3810, वाकणकर ब्रिज से गऊघाट स्टॉपडेम तक 2938 मीटर, चक्रतीर्थ से ऋणमुक्तेश्वर ब्रिज तक 1590 मीटर, भर्तृहरि गुफा और सिद्धवट से नागदा बायपास तक 11442 मीटर और शनि मंदिर से गोठडा बैराज तक 760 मीटर इस तरह कुल लगभग 29 हजार 215 मीटर की लम्बाई में घाटों के निर्माण के कार्य सम्पन्न होंगे।

खदान में डूबने से दो भाइयों की मौत

छोटे को बचाने बड़ा भाई भी कूदा, श्योपुर में अवैध खदान में भरा था बारिश का पानी

श्योपुर (नप्र)। श्योपुर के ओछपुर की खदान में दो नाबालिग की डूबने से मौत हो गई। दोनों चचेरे भाई थे। 12 साल का बच्चा खदान के पास खड़ा था, उसका पैर फिसला और पानी में जा गिरा। ये देख 17 साल का उसका भाई बचाने के लिए पानी में कूद गया। ओछपुरा में मो रोड के पास अवैध पत्थर खदान है। ओछपुरा थाना प्रभारी जय सिंह रघुवंशी ने बताया, बुधवार सुबह करीब 9 बजे धर्मेन्द्र (12) और रामवतार माली (17) रिस्तेदार के साथ बकरियां चराने खदान के पास गए थे।

मोदी सरकार की गठबंधन नीति

अपनों को हटाया, सहयोगियों को लाए, नीति आयोग में नई एंट्री

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को बतौर पदेन सदस्य शामिल किया



नई दिल्ली (एजेंसी)। सरकार ने नीति आयोग का पुनर्गठन किया है। नई सरकार बनने और मंत्रिपरिषद में कुछ नए मंत्रियों को जगह मिलने के बाद आयोग का पुनर्गठन किया गया है। आयोग के उपाध्यक्ष और पूर्णकालिक सदस्यों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। हालांकि इस पुनर्गठन में सहयोगी दलों के सदस्यों की भी एंट्री हुई है। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में बीजेपी अपने सहयोगी दलों का खासा ध्यान रख रही है। सहयोगी दलों के पांच मंत्री हुए शामिल- सरकार ने मंगलवार जिस नीति आयोग का पुनर्गठन किया उसमें आमंत्रित सदस्यों की संख्या 5 से बढ़ाकर 11 कर दी गई है। इसमें बीजेपी के सहयोगी दलों के पांच

मंत्री - एच डी कुमारस्वामी (जेडीएस), जीतन राम मांझी (एचएमएम), राजीव रंजन सिंह (जेडीयू), के आर नायडू (टीडीपी) और चिराग पासवान (एलजेपी-राम विलास) शामिल हैं। जिन सहयोगी दलों को शामिल किया गया है, उनमें कुमारस्वामी के पास भारी उद्योग और इस्पात विभाग है, मांझी के पास सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग है, राजीव रंजन सिंह उर्फ लालन सिंह के पास मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी विभाग है, नायडू के पास नागरिक उड्डयन विभाग है और चिराग पासवान के पास खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विभाग है। किसको इस बार नहीं मिली जगह- केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और अश्विनी वैष्णव, जो पहले विशेष आमंत्रित थे, इस बार सूची में नहीं हैं। गडकरी, वीरेंद्र कुमार और राव इंद्रजीत सिंह भी पहले विशेष आमंत्रित थे। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को बतौर पदेन सदस्य शामिल किया गया है।

डेवकन-डायरी

- डॉ. सुधीर सक्सेना

लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं।



यह सियासी समीकरणों का नया दौर है, दक्षिनी राज्यों में बनते-बिगड़ते समीकरणों का दिलचस्प दौर। रास्तों पर फिसलन है और वक्त की दरो- दीवार पर अटकलों के सब्जे उग आये हैं। सियासत भी परखनली की मानिंद है, जिसमें क्रियाएं लगातार होती रहती हैं। क्रियाएं तब भी बदस्तूर हो रही होती है, जब हमें सतह पर अवक्षेप नजर नहीं आता। यह भी गौरतलब है कि बहुतेरी घटनाएं इनमें उभरेक का काम करती है और पारस्परिक क्रिया-प्रतिक्रिया को मंद या तीव्र कर देती हैं। छहों दक्षिनी राज्यों में इन दिनों यही हो रहा है। लोकसभा- चुनाव के नतीजों के बाद भी यह दौर थमा नहीं है, बल्कि यह एक ऐसे नये पेचीदा गलियारे में खुला है, जिसमें घुमावदार गलियां हैं और कुलियां भी। यही वह सदर्भ है, जो राजनीति में अनिश्चितता, उत्सुकता और उत्तेजना का खमीर उपजाता है।

बात वर्णमाला के पहले अक्षर ‘अ’ यानि आंध्र से शुरू करें, जहां चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व में तेलुगुदेशम गठबंधन हाल में सत्ता में आया है। चंद्रबाबू विजनरी-नेता हैं। वह रफ्तार और नतीजों में यकीन रखते हैं। जुलाई को वह विशाखापटनम में एएमटीजेड के समारोह में थे। उनके साराभित संबोधन ने इस बात को बरबस दर्शाया गया कि उन्हें विकास-पुरुष क्यों कहा जाता है? चंद्रबाबू ने नायाब उपलब्धियों के लिए एएमटीजेड के संस्थापक सीईओ डॉ. जितेन्द्र शर्मा की मुक्तकंठ सराहना की और पीठ थपथपायी, जिन्हें उन्होंने इस्पात संयंत्र के समीप करीब 270 एकड़ ऐसी भूमि आवबंटीत की थी, जहां न सड़क या पार्इंड्री, न चांपाकल या बिजली का खंबा, और न ही झोपड़ी या कोई रिहाइश। और तो और डॉ. शर्मा की चुनी इस भूमि का कोई पिनकोड नंबर भी नहीं था। लेकिन आज वहां अत्याधुनिक और चित्ताकर्षक परिसर में विश्व की 140 से अधिक चुनिंदा कंपनियां कार्यरत हैं। डॉ. शर्मा ‘मेड टेक’ मेन कहे जाते हैं। हेल्थकेयर की दुनिया में एएमटीजेड की अपनी प्रतिष्ठ है और उसकी बढौलत भारत वहां शीर्षस्थ देशों में शुमार है। सौचिये कि क्या यह गौरवपूर्ण और श्रेष्ठ मानकों की रचना-यात्रा

चंद्रबाबू नायडू की वैज्ञानिक सोच और औदार्य के बिना संभव थी? बाबू ने इसे चिकित्सा प्रौद्योगिकी का हब बनाने का सुझाव दिया, आर्टीफिशियल इंटेलीजेंस की बात की, स्वर्णिम युग का आह्वान किया और जाहिर है कि इर संभव मदद का आश्वासन भी। वाइजैग-प्रसंग का जिक्र इसलिये कि विकास के प्रति गहरी वचनबद्धता ही वह कारक है, जो अप्रत्याशित चुनाव के बाद तमाम अटकलों के घटाटोप में भी बाबू को बीजेपी से जोड़े हुए हैं। यह नये समीकरणों का का ही तकाजा है कि गहन संशयों के बीच चंद्रबाबू ने समर्थन के बदले सौदा को कोई तरजीह नहीं दी। उन्होंने टीडीपी के लिए स्पीकर या डिप्टी स्पीकर अथवा मलाईंदार महकमों की कोई मांग नहीं की। उनके बयानों से साफ है कि वह प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी के प्रति गहरी कृतज्ञता और पवन कल्याण के प्रति गहरी आत्मीयता से भरे हुए हैं। तय है कि जोड़का की यात्रा जारी रहेगी। चंद्रबाबू की अभी तात्कालिक और पहली वरीयता आंध्र की वित्तीय स्थिति को पटरी पर लाना है।

उन्हें कर्ज की गटरी तले दबा जर्जर प्रदेश विरासत में मिला है, जहाँ उन्हें अपने वायदों और सपनों को अमली जामा पहनाना है। यकीनन विशेष राज्य का दर्जा (एससीएस) का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा है, जिस पर करीब पांच साल पहले उन्होंने मोदी सरकार से समर्थन वापस लिया था। बाबू बखूबी जानते है कि केन्द्र सरकार किसी भी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा देने के मूड में नहीं है। यूं भी यह बरं के छते में हाथ डालने जैसा होगा। 5 और 6 जुलाई को बाबू दिल्ली में थे। उन्होंने आंग्ल- दैनिक ‘द हिन्दु’ से बातचीत में कई माकें की बातें कहीं। वह अपने चौथे मुख्यमंत्रित्व काल को पूर्वापेक्षा और सबसे कठिन मानते हैं। उन्होंने दो-टूक कहा कि जरूरत एसीएस की मांग से कहीं बड़ी है। सूबे में हरेक संस्थान को पुनर्रचना और पुनर्निर्माण की जरूरत है। उन्होंने खरोंच नहीं, बल्कि उसके काफी नीचे से शुरूआत करनी पड़ रही है। अपने दो दिनी प्रवास में चंद्रबाबू सूत्री सीतारामण और जेपी नड्डा समेत छह केंद्रीय मंत्रियों से मिले। उन्हें अमरावती और पोलावरम समेत समग्र विकास की चिंता है। वह बुंदेलखंड सरीखा

सियासी समीकरणों का नया दौर

बात वर्णमाला के पहले अक्षर ‘अ’ यानि आंध्र से शुरू करें, जहां चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व में तेलुगुदेशम गठबंधन हाल में सत्ता में आया है। चंद्रबाबू विजनरी-नेता हैं। वह रफ्तार और नतीजों में यकीन रखते हैं। जुलाई को वह विशाखापटनम में एएमटीजेड के समारोह में थे। उनके सारगर्भित संबोधन ने इस बात को बरबस दर्शाया गया कि उन्हें विकास-पुरुष क्यों कहा जाता है? चंद्रबाबू ने नायाब उपलब्धियों के लिए एएमटीजेड के संस्थापक सीईओ डॉ. जितेन्द्र शर्मा की मुक्तकंठ सराहना की और पीठ थपथपायी, जिन्हें उन्होंने इस्पात संयंत्र के समीप करीब 270 एकड़ ऐसी भूमि आवंटित की थी, जहां न सड़क या पगड़ड़ी थी, न चांपाकल या बिजली का खंबा, और न ही झोपड़ी या कोई रिहाइश।



सेशल पैकेज चाहते हैं। उनका कहना है कि उनके वायदे उनके नहीं, वरन जोड़का के वायदे हैं।

चंद्रबाबू ने स्पष्ट कह दिया कि उनके और बीजेपी के दरम्या किसी ‘टकराव’ की हाल-फिलहाल कोई संभावना नहीं है। वह इसे बूझ रहे हैं कि बीजेपी के साथ रिश्तों में किसी तरह काटकटाव या किसी मुद्दे पर उतावलापन घाटे का सौदा होगा। आंध्र की घरेलू राजनीति का यही तकाजा है कि वह बीजेपी के साथ दोस्ताना रिश्ते कायम रखें और अपने वचनों को निभायें। यह बेतरह क्षीण हो चुकी जगनमोहन की वाईएसएस को कांग्रेस पार्टी को कोई भी मौका नहीं देना चाहते हैं कि वह पांव जमा सके। चंद्रबाबू यह भी जानते हैं कि कांग्रेस आंध्र में वापसी के लिए लालाथित और सचेष्ट है और यह भी कि स्व. राजशेखर रेड्डी के प्रति आंध्रजनों के मन में अभी भी श्रद्धा और सम्मान है। आंध्र में कांग्रेस ने पार्टी की कमान स्व. राजशेखर रेड्डी की बेटी शर्मिला को सौंपी है और उसे उम्मीद है कि वह आंध्र में कांग्रेस को पुर्नजीवित कर सकेगी। राहुल गांधी ने 8 जुलाई को उनकी 75वीं जयंती पर भावभीनी

श्रद्धाजलि अर्पित की और कहा कि यदि याईएसआर जीवित होते तो आंध्र की दशा सर्वथा भिन्न होती। याईएसआर को जन-नेता निरूपित करते हुए राहुल ने कहा कि उन्होंने उनसे बहुत कुछ सीखा। यहाँ तक कि उन्हें कन्याकुमारी से कश्मीर तक की भारत जोड़ो यात्रा की प्रेरणा रेड्डी गारू की प्रजा प्रस्थानम पदयात्रा से मिली थी। इसी रोज सोनिया गांधी ने भी अपना स्मृति-संदेश भेजा।

सुश्री शर्मिला लोकसभा चुनाव में असफल रहीं, किंतु कांग्रेस नेतृत्व को उनसे बड़ी उम्मीदें हैं। सुश्री शर्मिला भी लगातार पिता की विरासत के उत्तराधिकार का दावा कर रही हैं। जगन के नेतृत्व में याईएसएसआर कांग्रेस पार्टी को हशिये में सरकने को कांग्रेस आपदा में अवसर के तौर पर देख रही है। इसी के चलते तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी और उपमुख्यमंत्री भट्टी विक्रमार्क ने कांग्रेस के पूर्व नेताओं से खुली अपील की है कि इंदिराम्मा राज्यम की मजबूती के लिए वे लोग कांग्रेस में लौट आयें।

चंद्रबाबू इस घटनाक्रम के प्रति सचेत है और वह कदाई नहीं चाहेंगे कि बीजेपी और जनसेना पार्टी के साथ उनकी पार्टी के

गंठजोड़ पर आंच आयें। बिलाशक समीकरण बदल रहे हैं। केंसीआर और जगन की पार्टियां क्रमशः तेलंगाना और आंध्र में गर्दिश के दौर से गुजर रही हैं। तेलंगाना में विधान परिषद में भारत राष्ट्र समिति के 6 विधायक कांग्रेस में शरीक हो गये हैं। इससे परिषद में कांग्रेस की सदस्य संख्या बढ़कर 12 और बीआरएस की घटकर 21 रह गयी है। डी. विठ्ठल (आदिलाबाद), भानुप्रसाद (करीमनगर), प्रभाकर राव (रंगारेड्डी), ई. मल्लेशाम (बांग्गारपुर) दयानंद और बासवराजु सरैया के बीआरएस छोड़ने से निश्चित ही तेलंगाना में कांग्रेस का जनाधार मजबूत होगा। दिलचस्प तौर एमएलसी दो अन्य एमएलसी के. दामोदर रेड्डी और पी. महेंदर रेड्डी भी सदन में कांग्रेस सा आचरण कर रहे हैं। खबर गर्म है कि परिषद अध्यक्ष जी सुखेंदर रेड्डी भी कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं। उनका बेटा अमित रेड्डी पहले ही कांग्रेस में शरीक हो चुका है। गौरतलब है कि सुखेंदर रेड्डी कभी कांग्रेस के टिकट पर एम्पी चुने गये थे। बाद में वह की बीआरएस में चले आये। इस निष्ठा-परिवर्तन की ताजा कड़ी दिल्ली में देखने को मिली, जब बीआरएस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सदस्य के. केशवराव ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरौ की मौजूदगी में कांग्रेस ज्वाइन कर ली। इसके बाद उन्होंने अपना इस्तीफा सभापति जगदीप धनकड़ को सौंप दिया। तेलंगाना में दिनों-दिन दुबलाती बीआरएस की दिक्कत यह है कि उसकी नेत्री कविता पर केंद्रीय एजेंसियों ने जाल कस दिया है। बीआरएस के एक विधायक प्रकाश गौड़ पहले ही पार्टी छोड़कर कांग्रेस के पाले में जा चुके हैं।

उधर कांग्रेस में नरसापुरम के पूर्व सांसद के रघुरामकृष्ण राजू की शिकायत पर गुंटूर पुलिस ने पूर्व सीएम जगन और दो पुलिस अफसरों-पीवी सुनील कुमार और सीतारामंज -नेयुलु के खिलाफ उत्पीड़न का मामला दर्ज

कर लिया है। ज्ञातव्य है पूर्व सांसद ने याईएसआर सीपी छोड़कर टीडीपी का दामन थामा और अब वह उंडी से एमएलए है। उनका आरोप है कि पुलिस ने उन्हें सन् 2021 में अमानवीय यातनाओं को पार्टी के खिचड़ी दक्षिण के सिंहद्वार कर्नाटक में भी पक रही है। डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार को केतली से भाप को निकलने से रोकने में मशकत करनी पड़ रही है। वहाँ दोनों प्रमुख संप्रदाय-लिंगायत और वोक्ला्लिंगा अपने-अपने राजनीतिक हितों के मान से सचेत और मुखर है। स्थिति यह है कि शिवकुमार को पार्टी नेताओं को पार्टी के अंदरूनी मुद्दों पर सार्वजनिक बयान न देने की चेतावनी देनी पड़ी है। इस बीच कर्नाटक के नतीजे बीजेपी लिए भले ही आश्चस्तकारी रहे हो, किंतु कर्नाटक और केंद्र के रिश्ते और बिगड़ें हैं। राष्ट्रीय आपदा कोष से रकम के लिए कर्नाटक को सुप्रीम कोर्ट का द्वार खटखटाना पड़ा है। इस मद में कर्नाटक को केन्द्र से करीब 18,000 करोड़ रुपये लेने है, जबकि उसे बमुश्किल 3454 करोड़ रुपए मिले हैं। कर्नाटक का इसे ऊंट के मुंह में जीरा निरूपित करना सही है। दिलचस्प बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट में दस्तक तमिलनाडू और केरल ने भी दी है। केरल में कई बिल अभी भी गर्वनर की मेज पर अटक हैं और वित्तीय स्थिति विषम है। वाम नेताओं को उर सता रहा है कि लेफ्ट का यह आखिरा किला भी कहीं वह हाथ से गंवा न बैठे। मुख्यमंत्री स्टालिन अपने पते चतुराई से खेल रहे हैं। उन्होंने भी केंद्र पर मेट्रो रेल एवं अन्य परियोजनाओं के लिए फंड नहीं देने का आरोप लगाया है। उन्होंने रिटायर्ड जज सत्यानारायण की अध्यक्षता में केंद्र द्वारा पारित दंड विधानों की समीक्षा के लिए समिति का भी गठन किया है। उधर केरल में विजयन सरकार ने ईसाईयों को लुभाने को आयोग की सिफारिश लागू करने का फैसला किया है।

बेटा रखे समाज की नई नींव

हर काम की शुरुआत परिवार से ही होती है। हम यह भूल जाते है कि बेटियों की सुरक्षा की बात करते-करते हम बेटों को असुरक्षित कर रहे है। उनके भीतर के मानव मूल्य को बाहर ही नहीं आने दे रहे है। वह जितना बाहर से क्रूर हो रहे है उतना ही भीतर से टूट रहे है। यह क्रूरता उनका स्वभाव बन रही है। कभी भी किसी पर भद्दा कटाक्ष कर देना।

अभिव्यक्ति

अदिति सिंह भदौरिया

लेखक स्तंभकार हैं।

समाज के बदलते हुए स्वरूप को हम देख रहे है। हर पल एक डर रहता है की कि जाने कब क्या हो जाए? बेटियों को समय की हिदायत देना नहीं भूलते। जब तक बेटी घर वापिस ना आ जाए एक डर लगा सा रहता है। पर ऐसा क्यों है? क्यों हम बेटी पढाओ बेटी बचाओ के नारे को इतना जोर-शोर से कहने लगे है कि बेटों की परवरिश पर हम ध्यान ही नहीं दे पा रहे। क्या समाज में बेटों का योगदान मात्र वंश बढ़ाने तक रह गया है। परिवार की इज्जत, समाज में अपनेपन की जिम्मेदारी बेटों की नहीं है। हम क्यों यह भूल जाते है कि (अरे, वह तो लड़का है उसका कुछ नहीं जाएगा) यह वाक्य कहते समय हम सिर्फ उस लड़के की बात नहीं कर रहे। हम एक परिवार की, उनकी परवरिश की बात कर रहे है। तो जब लड़को से भी परिवार की इज्जत होती है तो उन्हें स्त्रियों की इज्जत करना सिखाना परिवार का ही पहला और महत्वपूर्ण काम है।

हर काम की शुरुआत परिवार से ही होती है। हम यह भूल जाते है कि बेटियों की सुरक्षा की बात करते-करते हम बेटों को असुरक्षित कर रहे है। उनके भीतर के मानव मूल्य को बाहर ही नहीं आने दे रहे है। वह जितना बाहर से क्रूर हो रहे है उतना ही भीतर से टूट रहे है। यह क्रूरता उनका स्वभाव बन रही है। कभी भी किसी पर भद्दा कटाक्ष कर देना। बहन हो या बेटी या फिर पत्नी कभी भी उस पर हाथ उठा देना। यहाँ तक की पूरे परिवार के सामने अपनी ही पत्नी का अपमान करना यह सब सामान्य नहीं है, बल्कि यह उनके भीतर के मानव के टूटने की शुरुआत है। जब भी कभी यह कहा जाए कि (कभी- कभार के झगड़े से कुछ नहीं होता, या फिर भाई है उसे ही पहले खा लेने दो) यह पहला चरण है लड़के का संवेदनहीन बनने की तरह यह उसका ही नहीं हमारा भी पहला कदम होता है,क्योंकि इस बात से हमारा बेटा ही रिश्तों से दूर नहीं होता बल्कि बेटी भी हीन भावना की तरफ बढ़ने लगती है। समाज के संतुलन को

बिगाड़ने की परिवार से ही पहल करते है। बेटों के प्रति प्राथमिकता परिवार के आर्थिक, धार्मिक, सामाजिक मापदंडों से प्रेरित होती है। जो पुरुष प्रधान समाज को दर्शाती है। लेकिन इसमें हानि पुरुषों की ही है। जिस प्रकार से आजकल बेटियों को बढ़ाने और उनके महत्व को दर्शाने की जबरदस्ती एक होड़ सी आ गई है। उसे देखकर विश्वास नहीं होता कि हम क्या परोस रहे है? परोस शब्द इसलिए कह रही हूँ कि एक तरफ तो पुरुष नए-नए तरीके खोज रहे है स्त्रियों के खिलाफ जिसे हम बहुत आसानी से अपने चारों तरफ हो रहे स्त्रियों के खिलाफ हो रहे आर्थमिक मामलों से देख सकते है। और दूसरी तरफ खुद को आगे रखने के लिए स्त्री ही स्त्री की दुश्मन होती जा रही है। विवाह पद्धती को ना मानना वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। रिश्तों में खटास का यह हाल है कि किसी के बुरे समय में भी उसका साथ ना देने में ज्यादातर लोग मानने लगते है।

समाज का पूरा संतुलन बिगड़ रहा है। लेकिन अभी भी हम बस भेदभाव में ही लगे हुए है। हम यह समझ ही नहीं पा रहे है कि जब प्रकृति ने दोनों को समान बनाकर भेजा है। तो खुद को किससे और क्यों वरिष्ठ साबित करने पर लगे हुए है? यदि हमें समाज को उन्नति की तरफ लेकर जाना है तो सबसे पहले घर में ही लड़कों को लड़कियों के प्रति सम्मान करना सीखाना होगा। जब एक मां यहाँ तक की सास भी अपनी बेटी और बहू की भावनाओं की कद्र करना अपने बेटों को सीखाएंगी तभी, वह घर से बाहर भी स्त्री को हाड-मांस का पुतला ना समझकर एक ईंसान के रूप में देख सकेगा और यह उसके पुरुष से मानव बनने की शुरुआत होगी। तब पहल होगी एक ऐसे समाज की जहां प्रगति का नाम सिर्फ भौतिकवाद से ही आगे बढ़ना नहीं है बल्कि सामाजिक एवम भंभावत्मक रूप से भी एक बेहद सफल समाज की नींव रखना है।

बेटों को बेटियों का महत्व समझाए जिससे की वह अपनी पत्नी यहाँ तक की अपनी साथी कुलींग और डेली ट्रांसपोर्ट में सफर करने वाली एक अनजान भी उनके साथ सुरक्षित महसूस सके। तभी यह बेटो बचाओ का नारा खत्म होगा और बेटे भी क़र्रता का दामन छोड़ समाज में अपना सही योगदान दे पाएंगे, तभी समाज के आगे बढ़ने का असली सफर शुरू हो सकेगा।

न्याय

अवधेश कुमार

लेखक पत्रकार हैं।

उच्चतम न्यायालय द्वारा मुस्लिम महिलाओं के गुजारे भत्ते के संदर्भ में दिए फैसले पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सहित कई मुस्लिम संस्थाओं और व्यक्तियों की प्रतिक्रिया ठीक वैसी ही है जैसे एक साथ तीन तलाक संबंधी फैसला पर थी। तलाकशुदा मुस्लिम महिलाएं दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत पति से गुजारा भत्ता मांग सकती हैं। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 तथा अब भारतीय न्याय संहिता धारा 144 में गुजारा भत्ता प्राप्त करने का प्रावधान है जो सभी विवाहित महिलाओं पर लागू होती है। निश्चित रूप से इस फैसले ने 1985 में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए शाहबानो मामले के फैसले की स्मृतियां ताजा कर दी है जब इसी तरह के फैसले के विरुद्ध देश भर में मुस्लिम संस्थाओं और संगठनों ने सड़कों पर विरोध प्रदर्शन शुरू किया था। सबका एक ही स्वर था कि न्यायालय हमारे मजहबी मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। हमारे परिवार , शादी विवाह ,तलाक, संपत्ति आदि मामले शरिया कानून के अनुसार चलेंगे और उसमें न्यायालय का हस्तक्षेप हमें स्वीकार नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने तब शाहबानो के पति मोहम्मद अहमद खान को धारा 125 के अंतर्गत गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया था। उसके बाद राजीव गांधी सरकार ने सन् 1986 में मुस्लिम महिला तलाक पर (अधिकारों का संरक्षण) कानून पारित कर इस फैसले को पलट दिया। उसमें इद्दत की अवधि, जो 90 दिन की होती है, के अलावा पतियों को गुजारा भत्ता देने की कानूनी अनिवार्यता से मुक्त कर दिया गया था। अब इन संगठनों और संस्थाओं की आक्रामकता में काफी कमी है,भाव लगभग वही है। क्या यह मान लिया जाए कि ये जो प्रतिक्रिया दे रहे हैं वही सही है? बिल्कुल नहीं।

वर्तमान फैसला 1986 के उसे कानून को भी कटघरे में खड़ा करने वाला है। वैसे वर्तमान फैसले में न्यायालय ने उसे कानून की भी व्याख्या की है। इस फैसले में 2019 में नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा एक साथ तीन तलाक रोकने के लिए बनाए कानून मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत दिए गए गैर कानूनी तलाक की पीड़िता के गुजारा भत्ते के बारे में भी व्यवस्था दी गई है। वास्तव में इस कानून के पीछे भी धारणा यही थी कि मुस्लिम महिलाएं मजहब की आड़ में शोषित और पीड़ित न हों। न्यायालय की यह टिप्पणी ध्यान देने योग्य है कि गुजारा भत्ता ख़ैरात नहीं है बल्कि महिलाओं का अधिकार है। वास्तव में इस फैसले से मुस्लिम विवाहित महिला विशेष कर तलाकशुदा मुस्लिम महिला के गुजारा भत्ता प्राप्त करने के कानूनी अधिकार पर इस फैसले से स्थिति स्पष्ट हो गई है।

हालांकि न्यायालय ने इस संबंध में कोई पहला फैसला नहीं दिया है। मुस्लिम महिला को भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 में गुजारा भत्ता प्राप्त करने के अधिकार पर पहले भी मुहर लगाई थी। इस फैसले में धारा 125 के तहत गुजारा भत्ता प्राप्त करने और शाहबानो फैसले के बाद आए 1986 के कानून पर तुलनात्मक विचार किया गया है जो पहले नहीं हुआ था। तो इसका कानूनी दृष्टि से महत्व यह है कि तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं के धारा 125 में गुजारा भत्ता प्राप्त करने को लेकर मौजूद कानूनी भ्रम खत्म हो गया है। मुस्लिम पुरुष इसी धारा की आड़ लेकर अपना बचाव करते थे। वर्तमान मामले में तेलंगाना के मोहम्मद अब्दुल समद ने भी इसी धारा की आड़ लेकर अपनी तलाकशुदा पत्नी को गुजारा भत्ता देने से बचने की कानूनी रणनीति अपनाई थी। वैसे 2001 में डेनियल लतीफी बनाम भारत संघ मामले में भी उच्चतम न्यायालय ने 1986 के कानून की व्याख्या करते हुए कहा था कि महिलाओं के अधिकार इद्दत की अवधि के आगे भी रहते हैं। उस फैसले के बाद ही अधिनियम में लागू की गई रोक एक तरह से अप्रभावी हो गई। ध्यान रखिए डेनियल लतीफी ने ही उच्चतम न्यायालय में शाहबानो के पक्ष में वकालत किया था। उच्चतम न्यायालय ने शाहबानो मामले में 1985 के फैसले में कहा था कि धारा 125 में मुस्लिम महिला भी पति से भरण पोषण पाने की हकदार है। जब 2017 के सायराबानो मामलों में उच्चतम न्यायालय ने एक साथ तीन तलाक को असंवैधानिक और अवैध करार दे दिया था तो अब महिलाओं के विरुद्ध फैसला आने का कोई प्रश्न नहीं था। 2009 में भी उच्चतम न्यायालय ने मौलाना अब्दुल कादिर मदनी मामले में कहा था कि रीलिजन का पालन करने के अधिकार में दूसरों के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करने का अधिकार शामिल नहीं है। लैंगिक समानता के परिप्रेक्ष्य में उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया था कि पर्सनल लॉ संवैधानिक अधिकारों के अनुरूप होना चाहिए। 2014 के शमीम

बानो बनाम अशराफ खान मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि मुस्लिम महिला तलाक के बाद भी अपने पति से गुजारा भत्ता पाने की हकदार है और मजिस्ट्रेट के न्यायालय के समक्ष इसके लिए आवेदन कर सकती है।

अब किसी महिला को तलाक के बाद मुस्लिम पति से गुजारा भत्ता लेने के लिए न्यायालय के समक्ष न इतने चक्कर काटने पड़ेंगे और न उन्हें इस तरह शरिया कानून से लेकर कानूनों की लंबी चौड़ी व्याख्या करना होगी। 1986 के कानून के रहते हुए भी मुस्लिम महिला को अब समस्या नहीं आएगी। 2019 के तीन तलाक विरोधी कानून तथा वर्तमान फैसला आगे से ऐसे सभी मामलों में न्यायिक फैसले का आधार बनेगा। यह मामला तेलंगाना से जुड़ा हुआ था। उच्च न्यायालय ने 13 दिसंबर , 2023 को मुस्लिम महिला को धारा 125 के तहत गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया था। मोहम्मद अब्दुल समद ने उसे फैसले के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की थी। हालांकि अभी अब्दुल समद के पास बड़ी पीठ में जाने का रास्ता बचा हुआ है किंतु वहां भी अलग कुछ होगा वह मानने का कोई कारण नहीं है। न्यायालय ने इसमें पहले के कई कानून और फैसलों की नए सिरे से व्याख्या कर दी है। न्यायालय ने स्पष्ट कहा है कि 2019 का मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण की धारा 5 के अंतर्गत मुस्लिम महिलाओं को गुजारा भत्ता पाने का अधिकार है या फिर वह महिला पूर्व की दंड प्रक्रिया धारा 125 तथा वर्तमान भारतीय न्याय संगीता 144 के तहत भी गुजारा भत्ता की मांग कर सकती है। अगर गुजारा भत्ता की अजी लंबित रहने के दौरान ही महिला को तीन तलाक दे दिया गया है तो वह धारा 125 में या फिर अधिनियम 2019 के अंतर्गत राहत मांग सकती है। इस तरह शीर्ष न्यायालय ने 2019 के कानून और धारा 125 के प्रावधानों को भी स्पष्ट कर दिया है और कहा है कि 2019 का कानून धारा 125 में उपलब्ध राहत के अलावा है। धारा 125 और मुस्लिम महिला तलाक पर अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 1986 दोनों के प्रावधान एक साथ लागू हो सकते हैं। न्यायालय का मानना है कि 1986 के कानून से धारा 125 में दिए गए अधिकार समाप्त नहीं होते हैं। पर्सनल लॉ के मुताबिक शादी करने वाली मुस्लिम महिला के पास दोनों कानून में गुजारा भत्ता प्राप्त का विकल्प व अधिकार है। यानी वह दोनों कानून में राहत मांग सकती है या दोनों में से किसी एक कानून में राहत ले सकती है।

इस तरह देखें तो न्यायालय ने खंड में व्याख्या करने की जगह अब तक के सभी फैसलों और संबंधित कानूनों को एक साथ मिलाकर निहितार्थ बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है। वस्तुत मुस्लिम संस्थाएं और संगठन एक साथ तीन तलाक और महिलाओं के अधिकार व गुजारा भत्ते पर अभी तक मजहब की झूठी आड़ लेकर मनमाना रवैया अपना रहे थे। अनेक मुस्लिम विद्वानों ने ही स्पष्ट किया तथा न्यायालय में साफ हो गया कि ऐसी कोई व्यवस्था शरिया में नहीं थी। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था एवं सत्ता तंत्र की मानसिकता ऐसी थी कि मुसलमान से संबंधित सामाजिक सुधार के विषय को छूने से समस्याएं बढ़ जाएंगी। सबसे ज्यादा भय मुस्लिम वोट खिसक जाने का था। राजीव गांधी को उनके लोगों ने यही समझाया तथा मुला मौलवियों से मिलाया था। तब राजीव सरकार में मंत्री रहे आरिफ मोहम्मद खान ने इसके विरुद्ध आवाज उठाई और मंत्री पद तक त्याग दिया। तब मुस्लिम समाज के अंदर उनकी सुनने वाले बहुत कम लोग थे। बाद के न्यायालयों के फैसलों ने साफ कर दिया की आरिफ मोहम्मद खान जैसे लोग ही सही थे और वही अपने समाज को सही दिशा देना चाहते थे तथा महिलाओं के गरिमा और सम्मान की रक्षा के साथ खड़े थे जो कहीं से भी इस्लाम विरोधी नहीं था दुर्भाग्य से आज भी भाजपा को छोड़ दें तो किसी राजनीतिक पार्टी ने उच्चतम न्यायालय के इस फैसले का खुलकर स्वागत नहीं किया है। सेक्यूलरवाद एवं अल्पसंख्यक संरक्षण के नाम पर झंडा उठाए हुए पत्रकारों की भी चुपची शर्मनाक है। कल्पना कीरंजि अगर आज केंद्र का सत्ता भाग्य के हाथों नहीं होती तो सरकार कितने बड़े दबाव में होती। अब समय बदल गया है। चक्र को मोड़ कर 1985 के शाहबानो मामलों तक नहीं ले जाया जा सकता। जब तीन तलाक की ही नरेंद्र मोदी सरकार ने संसद द्वारा गैर कानूनी करार देने का प्रस्ताव पारित कर दिया तो वहां से फिर पहले की अवस्था में सरकार लौटने की को सत्ता भी नहीं सकती। आज उच्चतम न्यायालय का फैसला संसद द्वारा नहीं पलटा जाएगा। यही बदला हुआ भारत है जिसको हर स्तर पर समझने और महसूस करने की आवश्यकता है।

समाजसेवी कन्नूलाल अग्रवाल नेहरू स्मृति महाविद्यालय के अध्यक्ष मनोनीत

सुबह सवरे सोहागपुर। समाजसेवी कन्नूलाल अग्रवाल जवाहरलाल नेहरू स्मृति महाविद्यालय का अध्यक्ष मनोनीत किया गया है। उल्लेखनीय है उक्त पद प्रदेश के विख्यात गृहस्थ संत पंडित मनमोहन मुदगल के ब्रह्मलीन होने से उक्त



अध्यक्षीय पद रिक्त था। इस संबंध में महाविद्यालय की शासी समिति के अध्यक्ष कैलाश पालीवाल ,सचिव हमीरसिंह चंदेल, वरिष्ठ समाजसेवी लक्ष्मी नारायण सोनी, विख्यात बुन्देली कवि पंडित राजेंद्र सहरिया , अभिषेक जैन ,विजय अग्रवाल, पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष अभिलाषसिंह चंदेल नेता वकील गोपाल मांहेधरी , वकील महेश पचौरी आदि उपस्थित थे। ज्ञातव्य है कि श्री अग्रवाल की गिनती उत्कृष्ट वक्ता के रूप में विख्यात हैं।आप धार्मिक, राजनीतिक एवं इतिहास पर धाराप्रवाह उद्बोधन देने के लिए जाने जाते हैं। आप सरस्वती शिशु मंदिर की नेताजी सुभाष चन्द्र बोस शिक्षा समिति के अध्यक्ष भी हैं। जवाहरलाल नेहरू स्मृति महाविद्यालय के अध्यक्ष मनोनीत होने पर वरिष्ठ पत्रकार अरुण पटेल, पूर्व पाषंद लक्ष्मी नारायण सोनी, पूर्व नपाध्यक्ष संतोष मालवीय, कृष्णा पालीवाल, राजा भैया पटेल, संजीव दुबे,अभिषेक जैन,जीवन जी दुबे, पूर्व व्यापारी संघ अध्यक्ष मुकेश मालवीय आदि स्नेहियों ने श्री अग्रवाल को बधाईयां दी हैं।

इंदौर में अंतरराष्ट्रीय मुशायरा 28 को

मोहन वर्मा। इंदौर की साहित्यिक, सांस्कृतिक और सांगीतिक संस्था ‘अदब की महफिल’ पूरे साल संगीत और कला प्रेमियों के लिए आयोजन करती है। इसी कड़ी में संस्था की 11 वीं सालगिरह के मौके पर ‘अदब की महफिल’ द्वारा अंतरराष्ट्रीय मुशायरे का आयोजन किया जा रहा है। 28 जुलाई रविवार शाम 5 बजे लाभ मण्डपम में होने वाले इस मुशायरे में देश विदेश के ख्यातनाम शायर,नेमान शौक नोएडा, मदन्मोहन दानिश ग्वालियर,अबरार काशिफ अमरावती,मुकेश आलम लुधियाना, सैय्यद सरोश आसिफ आबुधाबी,सुंदर मालेगांवी,जुबैर ताबिश जलगांव, इकरा अंबर गाजियाबाद तथा अश्वनी मिस्तल मुंबई शिरकत करेंगे।

मुहर्रम पर्व पर दृष्टिहीन बालिकाओं को भोजन कराया

देवास। दृष्टिहीन कन्या विद्यालय में मुहर्रम पर्व पर दृष्टिहीन बालिकाओं को भोजन और मिठाई बांटी गई। नईम एहमद ने बताया कर्बला की लड़ाई में इमाम हुसैन ने ईंसानियत को बचाया था, इसलिए मोहर्रम को ईंसानियत का महौना माना जाता है। इमाम हुसैन की शहादत और कुर्बानी की याद में मोहम्म मुनाया जाता है। इमाम हुसैन की शहादत की याद में मध्य प्रदेश दृष्टिहीन विद्यालय पर कार्यक्रम रखा गया । आज हमने भी एक कदम नेकी की तरफ बढ़ाकर अपना फर्ज निभाया और जो लोग दुनिया नहीं देख पाते हैं उनके साथ मोहर्रम पर्व मनाया गया, इस अवसर पर समाजसेवी अफजल खान (प्रकाश) ,वरिष्ठ कांग्रेसी नेता पंडित रितेश त्रिपाठी संस्था ब्राइट स्टार स्कूल अध्यक्ष सैयद मेशहर (जुगुनू), विजय सिंह चौहान (मोनु) , सरफराज अहमद सिद्दीकी,दिलनवाज, मोहन भाई ,अशरफ नागोरी, श्याम गोस्वामी, अब्दुल मलिक, मनोज कुशवाह, वसीम खिलजी। आभार उबेद शैख ने माना।

यह भी खूब..

माल तुलवा रहे साहब नौकरी जा रही सर्वेयर की..?



नर्मदापुरम। अपनी हरकतों से जिले में थू थू का विषय बन चुके उपसंचालक कृषि के कारण एक दिन पहले 17 सर्वेयर और एक सुपरवाइजर को नौकरी से निकाल दिया गया। सेवा से पृथक किए गए इन बेचारों पर आरोप है कि इन्होंने हैण्ड लिंग चालान की गुणवत्ता समय पर नहीं किया, एफ.ए.क्यू. मापदंड अनुसार खरीदी नहीं की.. बस इसलिए सेवा से पृथक कर दिए गए। इसका एक प्रेस नोट बाकायदा जनसंपर्क अधिकारी को भेजकर अपने हाथों अपनी पीठ थपथपा ली। एक दिन पहले ही पीएस ने यहां उपार्जन केंद्रों पर मूंग खरीदी का निरीक्षण किया और नियम विरुद्ध की गई खरीदी पर नाराजगी जताते हुए सर्वेयरों के सर पर नारियल फोड़ा। दोषी जबकि खुद डिप्टी डायरेक्टर ऐग्रिकल्चर है। 15 जुलाई को तो साहब ने केसला बीटीएस को फोन किया कि टूली का माल तुलवा ले। बीटीएम ने जबाव दिया साहब उसमें पूरी मिट्टी मिली हुई है। कहा ना तुलवा लो अब बीटीएस के पास इतना साहस कहा कि मिट्टी युक्त मूंग तुलवा नहीं पाये ऐसा एक जगह नहीं कई जगहों पर हुआ। अगर 15 तारीख की काल डिटेल निकलवाई जाए तो उपसंचालक कृषि और केसला बीटीएम की बातचीत निकल आयेगी। दरअसल उपसंचालक यहां सबकी नस जान गये। कलेक्टर को अपने वश में रखो फिर बाद में किसी को रोने मत दो। कलेक्टर नीरज सिंह के समय पर ही ऐसा कुछ हुआ था। रंगरलियां मनाते साहब की शिकायत हुई साहब के सरपरस्त अधिकारी की जांच डिप्टी कलेक्टर कोरी ने की मामला रफा-दफा हो गया.. मामला दबाने के लिए संबंधित महिला को मिट्टी परीक्षण केंद्र भेज दिया। जिसका वेतन मिट्टी परीक्षण केंद्र से बाकायदा निकल रहा। साहब के बंगले पर पहले गुलाबी गाड़ी जाती थी और अब सफेद मेस्ट्रो जाने लगी.. कलेक्टर की अनदेखी का दोहन कर रहे उपसंचालक कृषि खरीदी उपार्जन केन्द्र बनाने वेयरहाउस संचालकों से मोटी रकम वसूल लेते फिर खराब माल खरीद वाकर उन्हें ब्लैकमेल करते खराब माल खरीदी जांच में लेकर उन पर एफआईआर कराने की धमकी देकर डराते, इस मामले में अकेले उपसंचालक कृषि नहीं इनके साथ वेयरहाउसिंग प्रबंधक गावंडे भी शामिल हैं जहां जांच करते निकलता कुछ नहीं वह तो पीएस ने होशंगाबाद, निटया इटारसी में निरीक्षण कर गोलमाल पकड़ा और अधिकारी ने बचने में लिये सर्वेयर निपटा दिया।

ईमाम हुसैन की याद में मनाया गया मोहर्रम का पर्व



धार। धार शहर में ईमाम हुसैन की याद में मोहर्रम का पर्व मनाया गया । लोभान की खुशबू से महक रहे थे ताजिए। अकौदतमदों ने एक से बढ़कर एक आकर्षक ताजियों का निर्माण किया था। धार शहर भर में पुलिस प्रशासन ने चाक चौबंद व्यवस्था की थी।

आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर से बेटियों में आत्मविश्वास बढ़ता है

विपरीत परिस्थितियों से बचने के गुर सिखाएं



देवास। संस्था आस द्वारा सीआरवाय (चाइल्ड राइट्स एंड यू) प्रोजेक्ट के तहत शासकीय माध्यमिक स्कूल धनोरा में एक्सपर्ट मास्टर सईद आलम ने सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी। इस शिविर में अन्य स्कूल की छात्राओं ने भी भाग लिया। संस्था आस के डायरेक्टर वसीम इकबाल ने कहा कि देश के प्रसिद्ध सेल्फ डिफेंस एक्सपर्ट मास्टर सईद आलम ने बेटियों को दुश्मन पर काबू पाने की आसान तकनीक बताई। साथ ही उन्होंने विपरीत परिस्थितियों में पेन, चांभी, हेयर पिन और दुपट्टा को आत्मरक्षा के हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना सिखाया। प्राचार्य तेजसिंह राजपूत ने प्रशिक्षण शिविर में दी गई तकनीकों की प्रशंसा करते हुए कहा कि आज के समय में बच्चे, लड़कियां और महिलाओं को आत्मरक्षा के गुर सीखना चाहिए। सीआरवाय चाइल्ड राइट्स एंड यू के प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर यासमीन खान ने कहा कि आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर से बेटियों में आत्मविश्वास बढ़ता है। समापन

समारोह में भूमिका चौधरी, सोनाली पटेल, जीविका पटेल, वशिका चौधरी, लक्ष्मी चौधरी, ईशानी यादव, अपिता रावत, आस्था रावत, संजू जोशी, तनीषा चौधरी, वैशाली चौधरी, वर्षा चौधरी, प्रतिज्ञा पटेल, ऋषिका ठाकुर, माही पटेल और सुलोचना रावत ने बचाव के तकनीकों का शानदार प्रदर्शन किया। प्राचार्य तेजसिंह राजपूत ने सेल्फ डिफेंस एक्सपर्ट मास्टर सईद आलम और सहायक कोच अब्दुल राशिद को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। इस अवसर पर स्कूल के शिक्षक संतोष वर्मा, नम्रता नेमा और कुं. चेतना जामले खास उपस्थित थे। संचालन अंतिम झाला ने किया। आभार धर्मेन्द्र रावत ने माना।

फर्जी नाम से परीक्षा देने वाले आरोपी को कारावास व अर्थदण्ड की सजा

देवास। कृष्णाजीराव पवार महाविद्यालय में दिनांक 13/3/2019 को दोपहर 11 से 2 बजे के मध्य बी ए द्वितीय वर्ष की राजनीति विज्ञान के प्रथम प्रश्न पत्र परीक्षा में दिलवर सिंह के नाम से परीक्षा देने वाले आरोपी नरेंद्र सिंह राजपूत व दिलवर सिंह के विरुद्ध तृतीय सत्र न्यायालय में सत्र प्रकरण क्रं. 62/2023 अपराध धारा 419, 420, 465, 468, 471 भारतीय दण्ड संहिता व मद्र मान्यता प्राप्त परीक्षा अधि. 1937 की धारा 4 सह पठित धारा 3- घ के अन्तर्गत प्रकरण का विचारण पूर्ण होकर दिनांक 16/7/2024 को माननीय तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश राजेन्द्र कुमार पाटीदार के न्यायालय ने पुलिस थाना नाहर दरवाजा के अपराध क्र 72/2023 म प्र शासन ड्ड नरेन्द्र सिंह व दिलवर सिंह के प्रकरण मे शासन की ओर से प्रस्तुत समस्त साक्षीयो के कथनो व दस्तावेज से प्राप्त साक्ष्य का मुल्यांकन कर अपना निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाते हुऐ आरोपी नरेन्द्र सिंह को दोषी पाया गया। उसे धारा 419 में 3 वर्ष का सश्रम कारावास 2000/- अर्थ दण्ड, धारा 420 में 4 वर्ष का सश्रम कारावास 2000/- अर्थ दण्ड, धारा 465 में 2 वर्ष का सश्रम कारावास 2000/- अर्थदण्ड, धारा 468 में 4 वर्ष का सश्रम कारावास 2000/- अर्थदण्ड, धारा 471 के अपराध में 2 वर्ष का सश्रम कारावास 2000/- अर्थ दण्ड मद्र मान्यता प्राप्त परीक्षा अधि. 1937 की धारा 4 सह पठित धारा 3- घ में 2 वर्ष का सश्रम कारावास 1000/- अर्थदण्ड आरोपी को दी गई। सभी सजायें साथ-साथ भुगतायी जायेगी । आरोपी दिलवर सिंह साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त घोषित किया गया। शासन की ओर से प्रकरण में सफल अभियोजन अतिरिक्त लोक अभियोजक मनोज श्रीवास (शासकीय अभिभाषक) ने किया।

बाग में जीवाश्म उद्यान हेतु विकसित की जा रही विभिन्न साइट्स का किया अवलोकन

धार। मध्य प्रदेश इको टूरिज्म बोर्ड सीईओ समिता राजोरा, सीसीएफ इंदौर नरेंद्र कुमार सनोदिया, कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने आज बाग में स्थापित हो रहे राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान हेतु विकसित की जा रही विभिन्न साइट्स का अवलोकन किया गया। साथ ही इन साइट्स पर पर्यटकों को लाने के लिए आवश्यक सुविधाएं, साइट्स को संरक्षित करने तथा साइन बोर्ड लगाने के निर्देश दिए गए। राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान को आकर्षण का केंद्र बनाने के लिए तथा मानचित्र में बाग क्षेत्र में करोड़ों साल पुरानी जीवाश्मों के महत्व को आम जनता पहुंचाने के उद्देश्य से विशेष रुप से बीरबल साहनि इंस्टीट्यूट लखनऊ के निदेशक महेश ठक्कर एवं वैज्ञानिक शिल्पा शर्मा द्वारा सभी साइट्सस का अवलोकन किया गया। इस अवसर पर डीएफओ अशोक सोलंकी धार के जीवाश्म के विशेषज्ञ विशाल वर्मा, सहायक आयुक्त बृजकांत शुक्ला, डीएटीसीसी के प्रवीण शर्मा सहित अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे।



समस्या से निपटने के बजाय विभाग एक-दूसरे पर फोड़ रहे ठीकरा

परेशान होकर लोगों ने लिया 181 का सहारा जल भराव से जूझ रहे लोगों का कटाक्ष, कहा घर बैठें जनप्रतिनिधि

आमला। शहर में बरसों से चल रही कई समस्याओं और लोगों की मांग के बाद भी स्थानीय प्रशासन कुछ नहीं कर पा रहा है, तो लोग अब शासन के सहायता केंद्र 181 का सहारा लेने को मजबूर हो रहे हैं। बुधवार को शहर के अलग-अलग इलाकों में समस्याओं से जूझ रहे दर्जनों लोगों ने शासन के सहायता केंद्र 181 पर अपनी-अपनी शिकायतें दर्ज कराई हैं, साथ ही इलाकों में समस्याओं से जूझ रहे लोगों ने स्थानीय जनप्रतिनिधियों पर सवाल उठाते हुए उन्हें घर बैठने की सलाह तक दे डाली है। यहां सबसे पहले खबर में हम कुछ चुनिंदा लोगों को शामिल कर रहे हैं, जो लंबे समय से बेहद जरूरी स्थानीय समस्याओं पर आवाज उठाते रहे हैं, इनमें मनोहर चौहान, अरुण मथुरिया, अमरदीप तयवाड़े कृष्ण वर्मा, सुमित महतकर, परवेज खान, सलमान खान, आलोक मित्रा,विकास गर्ग, मोहम्मद सलीम, गन्ना, विजय कुमार, दीपक डेहरिया, राहुल अतुलकर, संगीता, ममता, रीना, नितेश साहू और न जाने ऐसे कितने ही लोग हैं जो स्थानीय प्रशासन की लापरवाही



से हर साल बारिश के दौरान जल भराव, जल जमाव, और अपने मकानों दुकानों में बारिश के पानी के भर जाने से इन लोगों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है।

निदान के बजाए एक दूसरे पर ठीकरा: दरअसल शहर में बीते तमाम दशकों में अब तक यही देखा गया है कि, स्थानीय लोगों को अपनी मामूली और बेहद जरूरी प्राथमिक समस्याओं के लिए यहां वहां गुहार लगाणा पड़ता है, और उस पर

अजीज खान का हज से वापिस आने पर भव्य स्वागत

हीरालाल गोलांनी सोहागपुर।

कांग्रेस के पूर्व वरिष्ठ पाषंद अजीज खान सपलीक किलापुरा निवासी मजीद खान की सपलीक एवं गांधी वार्ड निवासी लतीफ खान की सपलीक आज हज करने के उपरांत सोहागपुर वापसी हो गई। उल्लेखनीय है कि श्री खान करीबन 45 दिनों से अधिक समय मक्का मदीना धार्मिक यात्रा पर निकले थे। आज नगरागमन पर पूर्व नपाध्यक्ष संतोष मालवीय, पूर्व पाषंद लक्ष्मी नारायण सोनी,वरिष्ठ पाषंद जमील खान, कांग्रेस नेता नीरज चौधरी, ब्लाक कांग्रेस अध्यक्ष आलोक जायसवाल, अनेज जायसवाल, मक्का मदीना से अपने देश वापस



आ गए हैं, हज यात्रा से वापसी पर इनका गृह नगर एवं एवं वार्ड में भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान संतोष मालवीय जी, आलोक जायसवाल, गजेंद्र चौधरी, पाषंद जमील खान पाषंद प्रतिनिधि वसीम खान, हाजी शमीम पत्रकार, हाजी

नईम गुड्डा भाई, हाजी अब्दुल रशीद, बशीर मैनेजर, हाजी शहीद, इदरीश भाई ,खालिक पहलवान आदि शुभचिंतकों, वार्डवासियों एवं रिश्तेदारों ने बड़ी संख्या में उपस्थित होकर हाजियों का फूल-मालाओं के साथ स्वागत किया।

इस्कॉन मंदिर की भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा आज

विशेष प्रवचन के साथ लगेगा छप्पन भोग



देवास। प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी इस्कॉन मंदिर देवास द्वारा भगवान जगन्नाथ जी की भव्य रथ यात्रा का आयोजन 18 जुलाई को दोपहर 2 बजे किया जा रहा है। इस्कॉन देवास के आनंदमय दास ने बताया कि रथ यात्रा दोपहर 2 बजे रामेश्वर धाम मंदिर राम मंदिर से प्रारंभ होकर एबी रोड, सयाजी द्वार, तहसील चौराहा, नावेल्टी चौराहा, सुभाष चौक, जनता बैंक चौराहा, शालिनी रोड होते हुए मंडी धर्मशाला पहुंचेगी, जहां रथ यात्रा का विश्राम होगा। रथ यात्रा में प्राणेश्वर दास प्रभुजी रीजनल सेक्रेटरी इस्कॉन मद्र एवं गुरुदेव महामन प्रभुजी झोनल सेक्रेटरी इस्कॉन मद्र का सानिध्य प्राप्त होगा। रथ यात्रा के समापन अवसर पर मंडी धर्मशाला में विशेष प्रवचन होगा। साथ ही छप्पन भोग अर्पण के साथ शाम 7.30 बजे मंडी धर्मशाला में महाप्रसादी का वितरण होगा। कार्यक्रम के दौरान सांस्कृतिक प्रसंग, शास्त्रीय नृत्य, सुंदर भक्तिमय वाटिका, बच्चों की गतिविधियां, स्वादिष्ट मिठाई प्रसाद स्टॉल एवं पुस्तक स्टॉल आदि आयोजन होगा।

भाजपा मंडल कार्यकर्ता सुनिश्चित कर केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार करें : सावित्री ठाकुर केंद्रीय रायमंत्री

भाजपा राजगढ़ नगर मंडल की आवश्यक बैठक संपन्न

धार। भारतीय जनता पार्टी धार जिले के राजगढ़ नगर मंडल की आवश्यक बैठक मंगलवार को हनुमान मंदिर परिसर में आयोजित की गई जिसमें आगामी कार्यक्रमों पर विचार विमर्श किया गया साथ ही लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मिली ऐतिहासिक जीत पर बृथ के कार्यकर्ताओं को सम्मानित किए जाने का निर्णय लिया गया। बैठक में केंद्रीय राज्यमंत्री सावित्री ठाकुर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित होकर भाजपा मंडल कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। सावित्री ठाकुर ने कहा कि लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश में 29 सीट जीतकर इतिहास रचा है। इस लोकसभा क्षेत्र में दो लाख से अधिक मतों विजय होने पर मैं सभी मतदाता बंधुओं, माताओं एवं बहनों का हृदय से अभिनंदन के साथ-साथ आभार व्यक्त करती हूं। उम्मीद करती हूं कि जनता ने जो प्रचंड जनादेश दिया है हम उस पर खरे उतरेंगे। भाजपा मंडल का प्रत्येक कार्यकर्ता सुनिश्चित कर केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार करें। इस दौरान बैठक में मंचासीन भाजपा जिला उपाध्यक्ष एवं मंडल प्रभारी विश्वास पांडे,पुर्व संगठन जिला मंत्री उमाकांत भार्गव,भाजपा नेता राजेंद्र गर्ग ,नवीन बानिया,भाजपा जिला मीडिया प्रभारी संजय शर्मा, मंडल अध्यक्ष गिरधारी चौधरी सहित वरिष्ठ नेता उपस्थित थे। भाजपा जिला उपाध्यक्ष विश्वास पांडे ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक पेड़ मां के नाम अभियान को जन-जन तक पहुंचाने के लिए लोगों से पेड़ लगाने के लिए कार्य योजना बनाई गई। प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा प्रत्येक माह के अंतिम रविवार को होने वाली मन की बात कार्यक्रम को प्रत्येक बृथ पर सुनने की योजना बनाई गई। बैठक के अंत में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधा रोपण किया गया। इस अवसर पर ग्रामीण मंडल अध्यक्ष मदन चौधल वरिष्ठ नेता बाल सिंह वसुनिया मंडल उपाध्यक्ष गेंदालाल राठौर रामचंद्र धनेरिया,मंडल मीडिया प्रभारी शुभम संचालन निलेश सोनी व आभार रमेश राजपूत (पाषंद) ने किया।



जहां-जहां दिक्कतें हैं इसकी जानकारी बुलवाई जाएगी, विभागों को भी निर्देशित किया जाएगा, इसके अलावा पानी निकासी में अगर कहीं अतिक्रमण के चलते दिक्कतें हो रही है तो इसके लिए भी सूची बनाकर ऐसे लोगों के खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही भी की जा सकती है।

नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी जिला कलेक्टर, बैतूल

